

आयोजना 2015-2016 की विशेषताएं Highlights of Plan 2015-2016

वर्ष 2015-16 का आयोजनागत परिव्यय चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, राज्यों को केंद्रीय करों के 42% उच्च अंतरण को देखते हुए विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के लिए किए जाने वाले आवंटनों में संरचनात्मक बदलाव परिलक्षित करता है। इस महत्वपूर्ण उच्च अंतरण के परिणामस्वरूप, राज्य विषयों से संबंधित अनेक स्कीमों, केंद्रीय सहायता से बाहर हो जाएंगी। तथापि, इस तथ्य कि इन स्कीमों में से कुछ स्कीमों राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य से बनायी गयी स्कीमों, को ध्यान में रखते हुए, केंद्र ने यह निर्णय किया है कि ऐसी योजनाओं के लिए योगदान किया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, कानूनी बाध्यताओं के अधिदेश वाली स्कीमों और उपकर संग्रहण के उद्देश्य वाली स्कीमों के लिए पूर्णतया व्यवस्था की गयी है। केंद्र ने कुछ ऐसी योजनाओं के लिए भी पूर्णतया सहायता देने का निर्णय लिया है जो सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के फायदों के उद्देश्य की होती है। केंद्र प्रायोजित केवल 8 स्कीमों केंद्र की सहायता से हटेंगी। केंद्र प्रायोजित कुछ स्कीमों के मामले में, राज्यों का हिस्सा अधिक हो जाने से केंद्र: राज्य वित्तपोषण पद्धति में बदलाव होगा। विभाजन पद्धति में परिवर्तनों का ब्यौरा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा तैयार किया जाएगा। 2015-16 में आयोजनागत परिव्ययों का ब्यौरा निम्नवत है जिन्हें पृष्ठभूमि के रूप में देखा जाएगा।

अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने के लिए सरकार ने राजकोषीय दबाव के बावजूद पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि की है। सं.अ. 2014-15 में ₹192378 करोड़ के पूंजीगत व्यय की तुलना में 2015-16 में पूंजीगत व्यय ₹241431 करोड़ का होगा। यह 25.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

The Plan outlay of 2015-16 reflects the compositional shift in the allocations for various Programmes and Schemes in view of higher devolution; 42% of Union Taxes, to States as per the recommendation of 14th Finance Commission. Consequent to this substantially higher devolution, many schemes on the state subjects are to be delinked from Central support. However, keeping in mind that some of these schemes represent national priorities especially those targeted at poverty alleviation, Centre has decided that it will continue to contribute to such schemes. Besides, the schemes mandated by legal obligations and those backed by Cess collection have been fully provided for. Centre has also decided to support fully for some schemes which are targeted to the benefits of socially disadvantaged group. Only 8 Centrally Sponsored Schemes are to be delinked from support from the Centre. In case of some Centrally Sponsored Schemes, the Centre:State funding pattern will undergo a change with States to contribute higher share. Details of changes in sharing pattern will have to be worked out by administration ministries. The details of Plan outlays in 2015-16 indicated below are to be seen against this backdrop.

To enhance public spending in the economy, government has significantly enhanced the capital expenditure despite fiscal pressure. In comparison to capital spending of ₹192378 crore in RE 2014-15, the capital spending will be ₹ 241431 crore in 2015-16. This will be a growth of 25.5 per cent.

(₹ करोड़)	(₹ in Crore)
<p>महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना</p> <p>- 34699 वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसमें वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को राजी हों को 100 दिवस सवेतन रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करने हेतु। 01.04.2008 से ग्रामीण क्षेत्रों वाले सभी जिलों को नरेगा के अंतर्गत लाया गया है।</p> <p>राष्ट्रीय आजीविका मिशन (ग्रामीण एवं शहरी)</p> <p>- 3343 गरीब ग्रामीण तथा शहरी परिवारों को लाभप्रद स्व-रोजगार तथा कुशल मजदूरी रोजगार अवसरों की पहुंच से सशक्त बनाकर उनकी गरीबी दूर करने हेतु। यह समाज के दुर्बल वर्गों जिनमें अ.जा./अ.ज.जा., महिला, अल्पसंख्यक और निःशक्त व्यक्ति शामिल हैं, को पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करेगी।</p> <p>सभी के लिए आवास (शहरी और ग्रामीण)</p> <p>- 14200 गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को मकानों के निर्माण तथा कच्चे मकानों को पक्का करने हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए। घरों के निर्माण के लिए कुल आवंटन की 60% राशि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे अनु.जाति/अनु.ज.जाति के परिवारों के लिए है। सरदार पटेल शहरी आवास-निर्माण स्कीम शहरी गरीब व्यक्तियों की आवास आवश्यकताओं का समाधान करेगी।</p>	<p>Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme</p> <p>- 34699 for providing a legal guarantee of 100 days of wage employment in a financial year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. All the districts covering rural areas have been brought under NREGA with effect from 01.04.2008.</p> <p>National Livelihood Mission (Rural & Urban)</p> <p>- 3343 for reducing poverty by enabling the poor Rural and Urban households to access gainful self-employment and skilled wage employment opportunities. It would ensure adequate coverage of vulnerable sections of the society including SCs/STs, women, minorities and persons with disabilities.</p> <p>Housing for all (Rural and Urban)</p> <p>- 14200 for providing assistance to rural and urban BPL households for construction of houses and upgradation of kutchha houses. 60% of the total allocation is for construction of houses for BPL families of SCs/STs. Sardar Patel Urban Housing Scheme will address the housing requirement of urban poor.</p>

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

- 14291 अच्छी बारहमासी सड़कों के जरिए कनेक्ट न हुए पात्र ग्रामीण निवासियों हेतु कनेक्टिविटी की व्यवस्था कराने हेतु। मौजूदा ग्रामीण सड़कों का व्यवस्थित स्तरोन्नयन भी इस स्कीम का अनिवार्य भाग है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

- 9074 गरीबों को राज्यों द्वारा प्रदान किये जा रहे लाभों के अतिरिक्त सामाजिक सहायता हेतु न्यूनतम राष्ट्रीय मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए।
- **6000 स्वच्छ भारत**
- 2500 सभी ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयासों में राज्यों को सहायता देने के लिए राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम
- 3500 ग्रामीण स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान

सिंचाई**5300 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना**

- 1800 सूक्ष्म कृषि का विकास (प्रति बूंद अधिक फसल)
- 1500 एकीकृत जलसंभर विकास कार्यक्रम
- 2000 प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (त्वरित सिंचाई लाभ और बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम सहित)

कृषि**12257 कृषोन्नति योजना (केंद्र और राज्य)****जिसमें**

- 4500 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्य आयोजना)
- 2823 राष्ट्रीय फसल बीमा योजना हेतु
- 1300 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु
- 835 राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन

पशुपालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी

- 482 डेयरी विकास अभियान
- 411 नील क्रांति (अंतर्देशीय और समुद्री मात्स्यिकी सहित)

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण

- 90 भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकारों के लिए गोदामों के निर्माण हेतु।
- 155 भाण्डागारण क्षमता के निर्माण हेतु।
- 80 सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रचालनों के कंप्यूटरीकरण हेतु।

पर्यावरण एवं वन

- 688 वानिकी (राष्ट्रीय वनीकरण और परिस्थिति विकास) तथा वन्य जीवन हेतु।
- 758 पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण हेतु।

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम

- 1050 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु।
- 300 अवसंरचना विकास तथा क्षमता निर्माण हेतु।

उपभोक्ता मामले

- 120 उपभोक्ता जागरूकता तथा उपभोक्ता संरक्षण हेतु।
- 33 भारांश और उपायों के सुदृढीकरण हेतु।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

- 22000 सर्व शिक्षा अभियान हेतु।
- 8900 स्कूलों में मिड डे मील के राष्ट्रीय कार्यक्रम हेतु।
- 3565 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु।

उच्चतर शिक्षा

- 6705 तकनीकी शिक्षा हेतु।
- 3905 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हेतु।
- 1155 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान हेतु।
- 200 आईसीटी द्वारा शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन।

महिला एवं बाल विकास

- 8754 एकीकृत बाल विकास सेवाओं हेतु (आईसीडीएस)।
- 402 एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम हेतु।

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

- 14291 for providing connectivity to eligible unconnected rural habitations through good all-weather roads. The systematic upgradation of existing rural roads is also an essential component of the scheme.

National Social Assistance Programme

- 9074 for ensuring minimum national standard for social assistance to poor in addition to the benefits that States are providing.
- **6000 SWACHH BHARAT**
- 2500 National Rural Drinking Water Programme for supplementing the States in their effort to provide safe drinking water to all rural habitations.
- 3500 Swachh Bharat Abhiyan for rural sanitation.

IRRIGATION**5300 Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana**

- 1800 Development of Micro irrigation (per drop more crop)
- 1500 Integration Watershed Development Programme
- 2000 Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (including accelerated irrigation benefit and flood management programme)

AGRICULTURE**12257 Krishonnati Yojana (Centre and State)****of which**

- 4500 for Rashtriya Krishi Vikas Yojana (State Plan).
- 2823 for National Crop Insurance Programme.
- 1300 for National Food Security Mission.
- 835 for National Mission for Sustainable Agriculture.

ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

- 482 Dairy Vikas Abhiyan
- 411 Blue Revolution (including inland and marine fisheries)

FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

- 90 for construction of Godowns by Food Corporation of India/State Governments.
- 155 for construction of warehousing capacity.
- 80 for computerization of Public Distribution System operations.

ENVIRONMENT AND FORESTS

- 688 for Forestry (National Afforestation and Eco-Development) and Wild Life.
- 758 for Ecology and Environment.

MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

- 1050 for Prime Minister's Employment Generation Programme.
- 300 for Infrastructure Development and Capacity Building

CONSUMER AFFAIRS

- 120 for Consumer Awareness and Consumer Protection.
- 33 for strengthening Weights and Measures.

SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

- 22000 for Sarva Shiksha Abhiyan
- 8900 for National Programme of Mid Day Meals in Schools.
- 3565 for Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan.

HIGHER EDUCATION

- 6705 for Technical Education.
- 3905 for University Grants Commission.
- 1155 for Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan.
- 200 for National Mission in Education through ICT

WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

- 8754 for Integrated Child Development Services (ICDS).
- 402 for Integrated Child Protection Scheme.

- 438 इंदिरागांधी मातृत्व सहयोग योजना हेतु।
- 100 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान

सूचना प्रौद्योगिकी

- 2510 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों (अम्ब्रेला कार्यक्रम) हेतु।

दूर संचार

- 2400 सार्वभौमिक सेवाबाधता निधि (राष्ट्रीय और सुदूरवर्ती टेलीफोन) (ग्रामीण और दूरस्थ टेलीफोन)
- 2400 रक्षा सेवा नेटवर्क हेतु।

स्वास्थ्य

- 18000 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- 5174 चिकित्सा और जन स्वास्थ्य हेतु।
- 630 चिकित्सा संस्थाएं।

आयुष

- 137 आयुर्वेद प्रणाली के विकास हेतु।
- 89 यूनानी प्रणाली के विकास हेतु।
- 126 होम्योपैथी प्रणाली के विकास हेतु।
- 54 योगा तथा प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के विकास हेतु।

सूचना तथा प्रसारण

- 635 प्रसारण क्षेत्र हेतु।
- 71 सूचना क्षेत्र हेतु।
- 208 फिल्म क्षेत्र हेतु।

शहरी विकास

- 6000 शहरी पुनरुद्धार मिशन 500 बस्तियों और 100 स्मार्ट शहरों के विकास हेतु।
- 8385 मेट्रो रेल परियोजनाओं में इक्विटी निवेश के लिए।
- 200 राष्ट्रीय विरासत शहरों के कार्यक्रम हेतु।
- **40003 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

जिसमें

- 29420 टोल प्रेषण सहित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में निवेश हेतु।
- 1200 वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संबद्धता के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम हेतु।
- 4000 पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम।

विद्युत

- 4500 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हेतु।

कपड़ा

- 1520 प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम हेतु।
- 257 एकीकृत टेक्सटाइल पार्क हेतु।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता

- 1599 अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु।
- 885 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु।

निःशक्त मामले

- 125 विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता और उपकरणों हेतु
- 105 व्यक्तियों के लिए सहायता और उपकरणों हेतु

जनजातीय कार्य

- 1367 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक (I) के अंतर्गत स्कीम के लिए सहायता
- 1250 जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता।
- 1137 अ.ज.जा. के बच्चों की शिक्षा के लिए अंब्रेला योजना हेतु।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास

- 225 पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के तीव्र विकास के लिए पूर्वोत्तर सड़क निगम हेतु।
- 125 पूर्वोत्तर राज्यों में आर्गेनिक कृषि के उन्नयन हेतु।
- 90 संसाधनों (केन्द्रीय) के अ-व्यपगतनीय पूल हेतु।

अल्पसंख्यक मामले

- 1244 अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रक विकास कार्यक्रमों हेतु।

- 438 for Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana.
- 100 for Beti Bachao Beti Padhao Campaign

INFORMATION TECHNOLOGY

- 2510 Digital India Programme and telecommunication and Electronic Industries (Umbrella Programme)

TELECOMMUNICATIONS

- 2400 for schemes under Universal Service Obligation Fund (Rural and Remote telephony).
- 2400 for Network for Defence Services.

HEALTH

- 18000 National Health Mission.
- 5174 Medical and Public Health.
- 630 Medical Institutions.

AYUSH

- 137 for development of Ayurveda system.
- 89 for development of Unani system.
- 126 for development of Homoeopathy system.
- 54 for development of Yoga and Naturopathy system.

INFORMATION AND BROADCASTING

- 635 for broadcasting sector.
- 71 for information sector.
- 208 for film sector.

URBAN DEVELOPMENT

- 6000 Urban Rejuvenation Mission - 500 habitation and mission for development of 100 smart cities.
- 8385 for equity investment in Metro Rail Projects.
- 200 for National Heritage Cities Programme.
- **40003 MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS**

of which

- 29420 Investment of National Highways Authority of India including Remittance of Toll.
- 1200 Special programme for development of Road Connectivity in Left Wing Extremism (LWE) affected areas
- 4000 Special Accelerated Road Development Programme for North East Region.

POWER

- 4500 for Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana.

TEXTILES

- 1520 for Technology Upgradation Fund Scheme.
- 257 Development of mega clusters.

SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

- 1599 for Post-Matric scholarship for Scheduled Castes
- 885 for Post-Matric scholarship for Other Backward Classes

DISABILITY AFFAIRS

- 125 for Aids and Appliances for Handicapped
- 105 for various National Institutes for Disabled Persons

TRIBAL AFFAIRS

- 1367 Assistance for scheme under provisio (I) of Article 275 (1) of the Constitution.
- 1250 Special Central Assistance to Tribal Sub-plan
- 1137 Umbrella Scheme for Education of ST children

DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

- 225 for NE Roads Corporation for speedy development of roads in NE areas.
- 125 for promotion of Organic Farming in NE States.
- 90 for Non Lapsable Central Pool of Resources (Central).

MINORITY AFFAIRS

- 1244 for Multi-Sectoral Development Programmes for Minorities.

- 1540 मैट्रिकपूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
- गृह मंत्रालय**
- 990 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
- 150 मोबाइल वाहनों और नियंत्रण कक्षों द्वारा पीड़ितों से विपत्ति संकेतों के बैकएंड समेकन हेतु (निर्भया कोष से)।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- 600 विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड हेतु।
- 545 संबंध और आर एंड डी मिशन हेतु।
- 330 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रिम क्षेत्रों में बहु-विधा अनुसंधान हेतु (अनुसंधान और विकास सहायता)।
- 154 प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रमों हेतु।
- 137 तकनीकी अनुसंधान केंद्रों हेतु।

अंतरिक्ष

- 412 जीएसएटी-18 उपग्रह-प्रक्षेपण सेवाओं हेतु।
- 312 पीएसएलवी-सी परियोजना हेतु।
- 235 जीएसएटी-17 उपग्रह-प्रक्षेपण सेवाओं हेतु।
- 195 जीएसएलवी-परिचालन (एमके-III परिचालन सहित) हेतु।
- 120 जीएसएलवी एमके-III विकास हेतु।
- 150 सेमी क्रायोनिक इंजन विकास हेतु।
- 120 सेकेन्ड व्हीकल ऐसम्बली निर्माण
- 120 नेवीगेशनल उपग्रह प्रणाली
- 120 जीएसएटी-15 उपग्रह हेतु।

नागर विमानन

- 2500 एयर इंडिया लि. में इक्विटी प्रदान करने हेतु।

परमाणु ऊर्जा

- 3819 अनुसंधान और विकास हेतु।
- 940 उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं हेतु।
- 241 खनिज क्षेत्र की परियोजनाओं हेतु।

नाभिकीय विद्युत

- 400 भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड को ऋण हेतु।
- 178 न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में निवेश हेतु।
- 120 परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत (कुडनकुलम) में पड़ोस विकास परियोजना

पृथ्वी विज्ञान

- 294 पोलर साईंस और क्रायोस्फीयर कार्यकलापों के लिए अनुसंधान सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु।
- 250 प्रचालनात्मक मौसमी सेवाएं व मानसून की भविष्यवाणी में सुधार के लिए वायुमंडलीय वेध प्रणाली नेटवर्क के सुदृढीकरण प्रचालन और अनुसंधान हेतु।
- 175 भूकंपीय व भू-विज्ञान अनुसंधान तथा एक्स्ट्रामुराल अनुसंधान को संवर्धन हेतु

खेल

- 100 जम्मू व कश्मीर में खेल सुविधाएं बढ़ाने की योजना हेतु।
- 100 युवा नेता कार्यक्रम की योजना हेतु।
- 100 युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान करने हेतु राष्ट्रीय खेल प्रतिभा अनुसंधान प्रणाली कार्यक्रम

संस्कृति

- 325 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हेतु।

रसायन और पेट्रो-रसायन

- 84 केन्द्रीय प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी संस्थान

भेषज

- 99 8 राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के लिए (एनआईपीईआर)।

- 1540 Pre and Post Matric scholarship.

HOME AFFAIRS

- 990 Border area development Programme.
- 150 for backend integration of distress signal from victims with mobile vans and control rooms (from Nirbhaya fund).

SCIENCE AND TECHNOLOGY

- 600 for Science & Engineering Research Board.
- 545 for Alliance and R&D Mission.
- 330 for multi-disciplinary research in frontier areas of Science & Technology (Research and Development Support).
- 154 for Technology Development Programme
- 137 for Technical Research Centers.

SPACE

- 412 for GSAT-18 Satellite - Launch Services.
- 312 for PSLV-C Project.
- 235 for GSAT-17 Satellite - Launch Services.
- 195 for GSLV - Operational (including Mk-III Operational).
- 120 for GSLV Mk-III Development.
- 150 for Semi Cryogenic Engine Development
- 120 for Second Vehicle Assembly Building
- 120 for Navigational Satellite System
- 120 for GSAT-15 Satellite

CIVIL AVIATION

- 2500 for equity infusion in Air India Limited.

ATOMIC ENERGY

- 3819 for Research and Development.
- 940 for Industries Sector Projects.
- 241 for Mineral Sector Projects.

NUCLEAR POWER

- 400 for loans to Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Ltd. (BHAVINI)
- 178 for investment under NPCIL
- 120 for Neighbourhood Development Project (in Kudankulam) under DAE

EARTH SCIENCES

- 294 for strengthening research facilities for the Polar Sciences and Cryosphere activities.
- 250 for augmentation, operation and maintenance of Atmospheric Observation Systems Network to improve operational weather services and monsoon forecast.
- 175 for Seismological and Geo Science Research and promote extramural research.

SPORTS

- 100 for the scheme of enhancement of Sports facilities at Jammu & Kashmir.
- 100 for the scheme of Young Leaders Programme.
- 100 National Sports Talent Search System Programme identifying young sporting talent.

RASHTRIYA KALA SANSKRITI VIKAS

- 325 for Archaeological Survey of India.

CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

- 84 for Central Institute of Plastics Engineering and Technology.

PHARMACEUTICALS

- 99 for 8 National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER).

उद्योग

- 1200 दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना हेतु।
- 310 निवेश संवर्धन/मेक इन इंडिया हेतु।
- 166 औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम हेतु।
- 150 पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश नीति हेतु।
- 150 भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम हेतु।

डाक

- 363 आईटी अधिष्ठापन और आधुनिकीकरण तथा डाक प्रचालनों हेतु।

वित्त

- 7940 बेसिल III मानकों के अनुपालन में सीआरएआर के संतोषजनक स्तर को बनाये रखने में उनकी सहायता करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनःपूँजीकरण हेतु।
- 1300 एक्विजिशन बैंक को उसकी प्रदत्त पूँजी बढ़ाने के लिए इक्विटी सहायता।
- 300 नबार्ड के शेयर पूँजी को अभिदान हेतु।
- 250 फैक्ट्रिंग हेतु ऋण गारंटी निधि की स्थापना के लिए सिडबी को वित्तीय सहायता हेतु।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार

- 2100 पवित्र गंगा की सफाई हेतु नमामी गंगे

श्रम और रोजगार

- 1291 असंगठित श्रमिक स्कीम हेतु सामाजिक सुरक्षा
- 220 बाल, महिला श्रमिकों की कार्यकारी परिस्थितियों में सुधार

नवीकरणीय ऊर्जा

- 2410 ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय विद्युत
- 131 ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा

(वास्तविक लक्ष्य)**उर्वरक**

- 133.83 लाख मी. डन नाईट्रोजनी उर्वरक उत्पादन लक्ष्यार्त
- 47.39 लाख मी. डन फास्फेटी उर्वरक उत्पादन लक्ष्यार्त

कोयला और लिग्नाइट

- 700 मि.टन वर्ष 2014-15 के दौरान कोयले की घरेलू उपलब्धता आंकी गई है, जो कोल इंडिया लि. और अन्य से पूरा करने का अनुमान है।
- 25.67 मिलियन टन लिग्नाइट उत्पादन का अनुमान वर्ष 2014-15 के दौरान।

इस्पात

- 33.00 मिलियन टन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क उत्पादन का लक्ष्य रखा गया।
- 18.95 मिलियन टन भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. और राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. द्वारा विक्रय योग्य इस्पात का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

- 4460 मेगावाट पवन, लघु पनबिजली, बायोमास विद्युत/सह उत्पादन, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा और सौर शक्ति से ग्रिड-इंटरएक्टिव विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए।

रेलवे

- 2500 किलोमीटर ट्रैक का नवीकरण।
- 1600 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण।
- 500 किलोमीटर का गेज परिवर्तन।
- 300 किलोमीटर नई लाइनें।
- 1000 किलोमीटर डबल लाइन करना।
- 636 अतिरिक्त लोकोमोटिव विनिर्माण।

INDUSTRY

- 1200 for Grants to Delhi Mumbai Industrial Corridor Project
- 310 for Investment Promotion/ Make in India.
- 166 for Industrial Infrastructure Upgradation Scheme.
- 150 for North East Industrial & Investment Policy
- 150 for Indian Leather Development Programme

POSTS

- 363 for IT induction, modernisation and postal operations.

FINANCE

- 7940 for recapitalisation of Public Sector Banks to help them maintain comfortable level of CRAR in compliance with Basel III norms.
- 1300 for equity support to EXIM Bank to increase its paid up capital.
- 300 for subscription to the share capital of NABARD.
- 250 for financial support to SIDBI to set up Credit Guarantee Fund for Factoring.

WATER RESOURCES RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

- 2100 Namami Gange for cleaning of the Holy Ganga

LABOUR AND EMPLOYMENT

- 1291 Social Security for Unorganized workers scheme
- 220 Improvement in working condition of Child Woman Labour

RENEWABLE ENERGY

- 2410 Grid Interactive and Distributed Renewable Power
- 131 Renewable Energy for Rural Applications

(Physical Targets)**FERTILIZER**

- 133.83 lakh MT of Nitrogenous Fertiliser production targeted.
- 47.39 lakh MT of Phosphatic Fertiliser production targeted.

COAL AND LIGNITE

- 700 million tones of domestic production of Coal has been estimated during 2014-15, which is projected to be met from Coal India Limited and others.
- 25.67 million tones of Lignite production estimated during 2014-15.

STEEL

- 33.00 million tonnes of Iron ore production targeted by National Mineral Development Corporation Ltd.
- 18.95 million tones of saleable steel production by Steel Authority of India Ltd. and Rashtriya Ispat Nigam Ltd. targeted.

NEW AND RENEWABLE ENERGY

- 4460 MW Grid-interactive Power capacity addition from wind, small hydro, biomass power/cogeneration, urban and industrial waste to energy and solar power.
- 1.10 lakh - construction of family type Biogas plants.

RAILWAYS

- 2500 kilometers of track renewal.
- 1600 kilometers of electrification.
- 500 kilometers of gauge conversion.
- 300 kilometers of new lines.
- 1000 kilometers of doubling.
- 636 locos additional manufacture.